अण्डमान निकोबार द्वीप समाचार

रजि.न.34300/80 संख्या 76 श्री विजय पुरम, गुरूवार, 19 मार्च 2026 web: dt.andamannicobar.gov.in 2.00 रूपए

भारतीय विमानन में यात्री सुविधा को मजबूत बनाना

किसी भी उड़ान में कम से कम 60 प्रतिशत सीटें निःशुल्क आवंटित की जानी चाहिए

नई दिल्ली, 18 मार्च।

भारत वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बनकर उभरा है, जहां उड़ान योजना के अंतर्गत हवाई यात्रा अधिक सुलभ और समावेशी होती जा रही है। भारतीय हवाई अड्डे आज प्रतिदिन पांच लाख से अधिक यात्रियों को संभालते हैं, जो इस क्षेत्र की तीव्र वृद्धि को दर्शाता है।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय की सर्वोच्च प्राथमिकता यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करना है। इसी प्रतिबद्धता के अनुरूप, मंत्रालय ने यात्रा को सुगम बनाने के लिए कई यात्री–केंद्रित पहल की हैं, जिनमें किफायती भोजन के लिए उड़ान यात्री कैफे, पुस्तकों तक निःशुल्क पहुंच के लिए लाईब्रेरी और हवाई अड्डों पर निःशुल्क वाई–फाई की सुविधा शामिल हैं।

यात्रियों की सुविधा, पारदर्शिता और सभी एयरलाइनों में प्रक्रियाओं की एकरूपता को और मजबूत करने के लिए, मंत्रालय ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) के माध्यम से निम्नलिखित निर्देश जारी किए हैं:

- सभी यात्रियों की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए किसी भी उड़ान में कम से कम 60 प्रतिशत सीटें निःशुल्क आवंटित की जानी चाहिए।
- एक ही पीएनआर पर यात्रा करने वाले यात्रियों को एक साथ बैठाया जाना चाहिए, अधिमानतः अगल–बगल की सीटों पर।
- खेल उपकरण और संगीत वाद्ययंत्रों की ढुलाई को लागू सुरक्षा और परिचालन नियमों के अधीन, पारदर्शी और यात्री–अनुकूल तरीके से सुगम बनाया जाना चाहिए। एयरलाइंस

को पालतू जानवरों की ढुलाई के लिए भी स्पष्ट और पारदर्शी नीतियां बनानी होंगी।

- यात्रियों के अधिकारों के ढांचे का कड़ाई से पालन, विशेष रूप से विलम्ब, रद्द होने और बोर्डिंग से इनकार किए जाने की स्थिति में।
- एयरलाइन वेबसाइटों, मोबाइल एप्लिकेशनों, बुकिंग प्लेटफॉर्मों और हवाई अड्डे के काउंटरों पर यात्रियों के अधिकारों का प्रमुखता से प्रदर्शन।
- यात्रियों के अधिकारों की स्पष्ट जानकारी क्षेत्रीय भाषाओं में दी जाए ताकि व्यापक पहुंच और जागरूकता सुनिश्चित हो सके।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने, पारदर्शिता सुनिश्चित करने, शिकायतों को कम करने और विमानन तंत्र में सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। (प.सू.का.)

"दिल्ली से द्वीप 2.0" अभियान

अण्डमान–निकोबार के युवाओं के लिए सेना भर्ती अवसरों का विस्तार

श्री विजय पुरम, 18 मार्च

रुदिल्लीसेद्वीप 2.0" अभियान भारतीय सेना की समावेशिता एवं राष्ट्रीय एकीकरण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जिसके माध्यम से देश के सुदूर क्षेत्रों तक पहुंच सुनिश्चित की जा रही है। मार्च, 2025 में प्रारंभ किया गया यह आठ माह का अभियान, क्षेत्रीय भर्ती कार्यालय, चेन्नई द्वारा संचालित किया गया, जिसका उद्देश्य अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के युवाओं के लिए भर्ती अवसरों को उनके निकट लाना था।

इस अभियान के अंतर्गत दो सेना भर्ती रैलियों का सफल आयोजन किया गया–नेताजी स्टेडियम, श्री विजय पुरम (8 से 10 अक्टूबर, 2025) तथा मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम, कैंपबेल बे (14 से 15 अक्टूबर, 2025)। विशेष रूप से, कैंपबेल बे में आयोजित रैली देश के दक्षिणतम छोर पर पहली अग्निवीर भर्ती रैली रही, जिसने निकोबार क्षेत्र के दूरदराज़ युवाओं को अपने ही क्षेत्र के समीप भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने का ऐतिहासिक अवसर प्रदान किया। इस पहल की सफलता को आगे बढ़ाते हुए, क्षेत्रीय भर्ती कार्यालय, चेन्नई ने "दिल्ली से द्वीप 2.0" अभियान प्रारंभ किया है, जिसका उद्देश्य सेना भर्ती वर्ष 2027 के लिए पात्र अभ्यर्थियों तक पहुंच को और सुदृढ़ करना तथा उनकी सहायता करना है।

सूचना के व्यापक प्रसार हेतु भारतीय सेना भर्ती अधिसूचना 2027 सभी ज़िला कलेक्टरों को भेजी गई है, साथ ही युवाओं में प्रसार के लिए एक संक्षिप्त जागरूकता वीडियो भी साझा किया गया है। इसके अतिरिक्त, ग्राम स्तर पर जागरूकता बढ़ाने के लिए भर्ती अधिसूचना से संबंधित पत्र ग्राम सरपंचों को प्रेषित किए गए हैं। संघ राज्य क्षेत्र के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में क्यूआर कोड सहित बैनर लगाए गए हैं, ताकि अभ्यर्थी आधिकारिक पंजीकरण पोर्टल तक आसानी से पहुंच सकें। इस अभियान को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तथा क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्तियों के माध्यम से भी समर्थन दिया जा रहा है।

दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों के अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए प्रेरक व्याख्यान आयोजित किए जा रहे हैं तथा पंजीकरण शिविर स्थापित किए जा रहे हैं, जहां इच्छुक अभ्यर्थियों को ऑनलाइन पंजीकरण पूर्ण करने में सहायता और भर्ती प्रक्रिया के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। ये शिविर निम्नलिखित स्थानों पर आयोजित किए जा रहे हैं:

- जेएनआरएम कॉलेज, श्री विजय पुरम
- महात्मा गांधी राजकीय महाविद्यालय, मायाबंदर
- राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, डिगलीपुर
- राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, निकोबार
- राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, स्वराज द्वीप
- राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, कैंपबेल बे

प्राप्त विज्ञप्ति में अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के पात्र युवाओं से आग्रह किया गया है कि वे इन सुविधाओं का लाभ उठाएं, शिविरों में मार्गदर्शन प्राप्त करें, अंतिम तिथि से पूर्व अपना पंजीकरण पूर्ण करें तथा अनुशासन, सम्मान और राष्ट्र सेवा से परिपूर्ण जीवन की ओर पहला कदम बढ़ाएं।

भर्ती संबंधी किसी भी जानकारी या सहायता के लिए अभ्यर्थी भर्ती कार्यालय (मुख्यालय), चेन्नई, फोर्ट सेंट जॉर्ज परिसर, चेन्नई–600009, तमिलनाडु, हेल्पलाइन नम्बर 044–25674924 पर संपर्क कर सकते हैं।

स्वराज द्वीप के एलीफेंट तट पर 'फ्लाई बोर्ड' गतिविधि का शुभारंभ

श्री विजय पुरम, 18 मार्च

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए स्वराज द्वीप के एलीफेंट तट पर आज "फ्लाई बोर्ड" नामक नई जल क्रीड़ा गतिविधि का शुभारंभ किया गया। इसका उद्घाटन श्री विनायक चमाड़िया (आईएएस), निदेशक (सूचना, प्रचार एवं पर्यटन), अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा संबंधित अधिकारियों एवं जल क्रीड़ा संचालकों की उपस्थिति में किया गया।

यह नई गतिविधि द्वीपसमूह के साहसिक जल क्रीड़ा विकल्पों में एक रोमांचक जोड़ है, जो पर्यटकों को एक अनूठा अनुभव प्रदान करेगी। इस गतिविधि में एक व्यक्ति को शक्तिशाली जल धाराओं के माध्यम से समुद्र की सतह के ऊपर उठाया जाता है, जिससे वह हवाई करतब करते हुए आसपास के सुंदर दृश्यों का आनंद ले सकता है। प्रशासन द्वारा निर्धारित सभी सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया गया है, जिसमें प्रशिक्षित कर्मियों की तैनाती एवं प्रमाणित उपकरणों का उपयोग शामिल है।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार सूचना, प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा नवाचारपूर्ण एवं उच्च रोमांचक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने के साथ–साथ स्थानीय युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर

भी सृजित हो सकें। फ्लाई बोर्डिंग की शुरुआत से अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के जल क्रीड़ा क्षेत्र में एक नया आयाम जुड़ने की उम्मीद है, जो पर्यटकों के समग्र अनुभव को और समृद्ध करेगा।

जंगलीघाट में स्ट्रीट वेंडर्स हेतु समर्पित ओपन मार्केट स्थल विकसित

श्री विजय पुरम, 18 मार्च

श्री विजय पुरम नगरपालिका परिषद (एसवीपीएमसी) ने सुव्यवस्थित शहरी प्रबंधन एवं जनसुविधा के प्रति अपनी निरंतर प्रतिबद्धता के अंतर्गत जंगलीघाट में स्ट्रीट वेंडर्स (रेहड़ी पटरीवालों) के लिए एक समर्पित ओपन मार्केट स्थल विकसित किया है, जहां वे परंपरागत रूप से रविवार को अपनी विक्रय गतिविधियां संचालित करते रहे हैं।

सभी स्ट्रीट वेंडर्स का इस नव–निर्धारित विक्रय स्थल, जंगलीघाट में स्वागत किया जाता है तथा उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है कि वे सभी लागू नियमों एवं प्रावधानों का पालन करते हुए इस संगठित ओपन मार्केट का उपयोग करें। यह स्थान सुनियोजित ढंग से विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य विक्रेताओं एवं आम जनता दोनों के लिए सुरक्षित, सुलभ एवं सुव्यवस्थित वातावरण प्रदान करना है, साथ ही आसपास के क्षेत्रों में यातायात की सुगमता एवं पैदल आवागमन को भी निर्बाध बनाए रखना है।

प्राप्त विज्ञप्ति में एसवीपीएमसी ने सभी संबंधित विक्रेताओं से अनुरोध किया है कि वे 22 मार्च, 2026 से प्रत्येक रविवार को इस सुविधा का पूर्ण उपयोग करें तथा जंगलीघाट में एक सुव्यवस्थित एवं सजीव ओपन मार्केट स्थापित करने में सहयोग प्रदान करें। आम जनता से भी अनुरोध किया गया है कि वे निर्धारित बाज़ार क्षेत्र में उपलब्ध सेवाओं एवं सुविधाओं का लाभ उठाएं तथा इस पहल को सफल बनाने में अपना सहयोग दें।

आईआईएचएमआर बेंगलुरु द्वारा अण्डमान–निकोबार में एलएएसआई वेव–2 सर्वेक्षण का शुभारंभ किया गया

श्री विजय पुरम, 18 मार्च

भारतीय स्वास्थ्य प्रबंधन अनुसंधान संस्थान (आईआईएचएमआर), बेंगलुरु ने अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में दीर्घकालिक वृद्धावस्था अध्ययन (एलएएसआई) के दूसरे चरण के अंतर्गत फील्ड अन्वेषकों के लिए एक गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया है। आईआईएचएमआर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वायत्त संगठन अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (आईआईपीएस) के मार्गदर्शन में अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के लिए फील्ड एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है।

एलएएसआई वेव–2 भारत में वृद्धावस्था पर केंद्रित एक प्रमुख अध्ययन है, जिसका उद्देश्य 45 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के वयस्कों तथा उनके जीवनसाथियों से संबंधित राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधिक आंकड़े एकत्रित करना है। सर्वेक्षण में तीन प्रकार की अनुसूचियाँ शामिल हैं–गृहस्थी, व्यक्तिगत तथा सामुदायिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण। गृहस्थी प्रश्नावली में आवास की स्थिति, जल, स्वच्छता एवं बिजली की उपलब्धता, उपभोग पैटर्न, संपत्ति एवं ऋण, आय तथा बीमा संबंधी विस्तृत जानकारी एकत्र की जाती है।

व्यक्तिगत साक्षात्कार में जनसांख्यिकी, कार्य इतिहास, सेवानिवृत्ति, स्वयं द्वारा बताए गए स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वास्थ्य, संज्ञानात्मक क्षमता, पारिवारिक एवं सामाजिक नेटवर्क तथा स्वास्थ्य सेवाओं के उपयोग से संबंधित जानकारी शामिल होती है। सर्वेक्षण में स्वास्थ्य मूल्यांकन भी शामिल है, जिसमें रक्तचाप, नाड़ी, हाथ की पकड़ की शक्ति, संतुलन, दृष्टि, लंबाई, वजन, कमर/कूल्हे का माप तथा स्पाइरोमेट्री के साथ प्रयोगशाला विश्लेषण हेतु ड्राइड ब्लड स्पॉट संग्रह किया जाता है।

हमारे फील्ड अन्वेषक उच्च गुणवत्ता वाले आंकड़े एकत्र करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो स्वस्थ एवं सक्रिय वृद्धावस्था के लिए नीतियों के निर्माण में सहायक होंगे। नामित मुख्य टीम में डॉ. ज्ञान चंद्र कश्यप (राज्य परियोजना समन्वयक), डॉ. स्नेहग्धा बिस्वास (राज्य स्वास्थ्य समन्वयक), डॉ. सार्थक सेनगुप्ता (राज्य आईटी समन्वयक), डॉ. कुमार चिमन सिन्हा (राज्य जनसांख्यिकी विशेषज्ञ) तथा श्री अभिषेक कुमार (अनुसंधान अधिकारी) शामिल हैं। इन सभी ने यह सुनिश्चित किया है कि प्रशिक्षण राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो तथा तीनों ज़िलों में समुदायों से उच्च गुणवत्ता के आंकड़े एकत्र किए जाएं।

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार आईआईएचएमआर अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में स्वास्थ्य सेवा निदेशालय एवं स्थानीय प्रशासन के सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता है। आईआईएचएमआर टीम ने 18 मार्च से फील्ड कार्य प्रारंभ कर दिया है और डेटा संग्रहण की प्रक्रिया जून के मध्य तक द्वीपों में जारी रहेगी, जिससे भारत की तेजी से बढ़ती वृद्ध आबादी के लिए साक्ष्य–आधारित योजना एवं संसाधन आवंटन में सहायता मिलेगी।

'नराकास' के सदस्य कार्यालयों के लिए राजभाषा नीति एवं ई–टूल्स पर कार्यशाला हुई

श्री विजय पुरम, 18 मार्च।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास), श्री विजय पुरम द्वारा अपने सदस्य कार्यालयों के लिए आज राजभाषा कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का विषय "राजभाषा नीति, उसका कार्यान्वयन तथा ई–टूल्स" था। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री राजेन्द्र इंदवार, उप सचिव (राजभाषा)/सचिव (नराकास) ने की, जिन्होंने दैनिक कार्यालयीन कार्यों में हिंदी के अधिक से अधिक प्रयोग को सुदृढ़ करने हेतु निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया और सभी उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों से कार्यशाला का पूरा लाभ उठाने का आग्रह किया।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार प्रारंभिक संबोधन श्री एस. मोहनदास, वरिष्ट अनुवाद अधिकारी द्वारा दिया गया, जिसमें उन्होंने राजभाषा की संवैधानिक स्थिति पर संक्षिप्त में जानकारी देते हुए इस प्रकार की कार्यशालाओं के आयोजन के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला तथा सभी उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यशाला में सक्रिय सहभागिता हेतु प्रेरित किया। कार्यशाला का संचालन श्री अजय सिंह, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी द्वारा किया गया, जिन्होंने राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन तथा सरकारी कार्यों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु ऑनलाइन ई–टूल्स के उपयोग पर विस्तार से प्रकाश डाला। नराकास, श्री विजय पुरम के विभिन्न कार्यालयों के अधिकारी एवं कर्मचारी इस कार्यशाला में उपस्थित रहे तथा चर्चाओं में सक्रिय भागीदारी कर कार्यक्रम को ज्ञानवर्धक और एवं सफल बनाया।

फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नाविक और जहाज़ सुरक्षित, कोई घटना नहीं : सरकार

नई दिल्ली, 18 मार्च।

सरकार ने बुधवार को कहा कि मध्य–पूर्व क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नाविक पूरी तरह सुरक्षित हैं और पिछले 24 घंटों में किसी भी भारतीय झंडे वाले जहाज से जुड़ी कोई घटना सामने नहीं आई है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि वर्तमान में पश्चिमी फारस की खाड़ी (पर्शियन गल्फ) क्षेत्र में 22 भारतीय जहाज और 611 भारतीय नाविक मौजूद हैं। नौवहन महानिदेशालय लगातार जहाज मालिकों, आरपीएसएल एजेंसियों और भारतीय मिशनों के साथ मिलकर स्थिति पर नजर बनाए हुए है।

एलपीजी टैंकर 'शिवालिक' और 'नंदा देवी', जो मध्य–पूर्व

से लौट चुके हैं, फिलहाल तय समय के अनुसार तेल कंपनियों के शेड्यूल के मुताबिक अपना कार्गो उतार रहे हैं। डीजी शिपिंग का कंट्रोल रूम चौबीसों घंटे काम कर रहा है।

शेष पृष्ठ 4 पर

सक्रिय सुरक्षाः बाराटांग पेट्रोल पंप पर मॉक फायर ड्रिल

मायाबंदर, 18 मार्च

मध्य अण्डमान के बाराटांग स्थित अग्निशमन केन्द्र द्वारा अनिडको पेट्रोल पंप, बाराटांग में प्रतिक्रिया समय, अग्निशमन दक्षता तथा कर्मचारियों के समन्वय का आकलन करने हेतु मॉक फायर ड्रिल आयोजित की गई। परिदृश्य में 40 केएल भूमिगत टैंक में डीज़ल भरने के दौरान ईंधन डिस्पेंसर लाइन में आग लगने की स्थिति को शामिल किया गया था। टीम ने तत्परता से प्रतिक्रिया दी और कॉल प्राप्त होने के 3 मिनट के भीतर स्थल पर पहुंच गई।

उत्तर व मध्य अण्डमान के पुलिस अधीक्षक से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार डिलीवरी होज़ और फोम कंपाउंड का उपयोग करते हुए अग्निशमन कार्य प्रारंभ किया गया तथा आग पर कुशलतापूर्वक काबू पाया गया। ड्रिल के पश्चात आयोजित सत्र में सुरक्षा प्रोटोकॉल, मुख्य सीख तथा प्राथमिक उपचार और अग्निशमन उपकरणों के उपयोग पर बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस

ड्रिल में कर्मचारियों, प्रबंधन और आम जनता की भागीदारी रही, जिससे ईंधन स्टेशनों पर सुरक्षा मानकों के प्रति जागरूकता, तैयारी और अनुपालन को बढ़ावा मिला।

जहाज़रानी सेवा निदेशालय द्वारा भूकंप मॉक ड्रिल का सफल आयोजन

श्री विजय पुरम, 18 मार्च

जहाज़रानी सेवा निदेशालय (डीएसएस) ने आज अपने मुख्य प्रशासनिक भवन परिसर में भूकंप मॉक ड्रिल का आयोजन किया। यह अभ्यास डीएसएस के आपदा प्रबंधन नोडल अधिकारी के पर्यवेक्षण में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य प्रशासनिक भवन, सूचना केंद्र एवं स्टार्स टिकटिंग काउंटर के सभी कर्मचारियों तथा निदेशालय की आपदा प्रबंधन टीम ने सक्रिय भागीदारी की। अभ्यास के अंतर्गत कुल 129 कर्मियों को निर्धारित सुरक्षित स्थल तक सफलतापूर्वक निकाला गया। मॉक परिदृश्य में एक घायल व्यक्ति के बचाव को भी शामिल किया गया, जिसे त्वरित प्राथमिक उपचार प्रदान कर प्रतिक्रिया दल द्वारा सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार पूरी प्रक्रिया समन्वित रूप से संपन्न हुई, जिसने प्रभावी प्रतिक्रिया प्रणाली एवं विभिन्न एजेंसियों के बीच उत्कृष्ट सहयोग का प्रदर्शन

किया। डीएसएस के उप निदेशक (प्रभारी) के समग्र पर्यवेक्षण में अभ्यास पूर्ण होने के पश्चात स्थिति सामान्य घोषित की गई और सभी कर्मचारी सुरक्षित रूप से अपने–अपने कार्यस्थलों पर लौट आए।

'डीब्राइट' की एनएसएस यूनिट–2 द्वारा अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित

श्री विजय पुरम, 18 मार्च

डॉ. बी.आर. प्रौद्योगिकी संस्थान (डीब्राइट) के सभागार, श्री विजय पुरम, दक्षिण अण्डमान में 18 मार्च, 2026 को एनएसएस अभिमुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एनएसएस स्वयंसेवकों, संकाय सदस्यों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों तथा विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने सक्रिय भागीदारी की। कार्यक्रम में लगभग 500 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया।

इस सत्र की शोभा डॉ. सी. सैमुअल चेल्लैया, क्षेत्रीय निदेशक, एनएसएस क्षेत्रीय निदेशालय, चेन्नई, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने बढ़ाई। उन्होंने एनएसएस योजना के महत्व, उसकी गतिविधियों, पुरस्कारों तथा अनुशासन, स्मार्ट वर्क और चरित्र निर्माण के मूल्यों पर विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान किया।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार कार्यक्रम का स्वागत डॉ. ई. मुथु कुमारन, एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी (यूनिट–2) द्वारा किया गया तथा समन्वयन श्रीमती अनुपमा राय,

सहायक प्राध्यापक (रसायन विज्ञान) द्वारा किया गया। यह कार्यक्रम अत्यंत ज्ञानवर्धक एवं प्रभावशाली रहा, जो एनएसएस के आदर्श वाक्य "स्वयं से पहले आप" की भावना को प्रतिबिंबित करता है।

वन स्टॉप सेंटर द्वारा स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत व्यापक जागरूकता एवं स्वच्छता गतिविधियां चलाई गई

श्री विजय पुरम, 18 मार्च

समाज कल्याण निदेशालय के वन स्टॉप सेंटर द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान व्यापक जागरूकता एवं स्वच्छता गतिविधियों का आयोजन किया गया। 1 से 15 मार्च तक अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में विभिन्न स्थानों पर स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने हेतु अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन गतिविधियों में रांची बस्ती के आंगनवाड़ी केंद्र में जागरूकता सत्र, नयागांव आंगनवाड़ी केंद्र, नयाशहर सामुदायिक भवन तथा जंगलीघाट में स्वच्छता अभियान शामिल रहे, जिससे स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण को बढ़ावा मिला।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार थोराटांग नाला क्षेत्र में महिलाओं एवं किशोरियों के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता, मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन एवं स्वच्छता व्यवहार पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कालीकट सामुदायिक भवन में संवाद सत्र आयोजित किया गया तथा

नमूनाघर में स्वच्छता अभियान के साथ वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया गया। गांधी नगर ग्राम पंचायत में भी जागरूकता सत्र आयोजित कर प्रतिभागियों को सही हाथ धोने की विधि, सेनेटरी पैड के उपयोग के महत्व एवं व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने के बारे में जानकारी दी गई।

आपूर्ति गोदामों व पीडीसी में लेनदेन अस्थायी रूप से स्थगित रहेगा

श्री विजय पुरम, 18 मार्च

नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा संघ राज्य क्षेत्र के विभिन्न भागों में स्थित अपने सभी गोदामों/पीडीसी का वार्षिक भौतिक सत्यापन 25 मार्च, 2026 से 31 मार्च, 2026 तक किया जाएगा। प्राप्त विज्ञप्ति में आम जनता एवं सभी हितधारकों को सूचित किया गया है कि इस अवधि के दौरान सभी प्रकार के लेन–देन 25 मार्च, 2026 से 31 मार्च, 2026 तक अस्थायी रूप से स्थगित रहेंगे।

द्वीपों के टेटे खिलाड़ियों का राष्ट्रीय प्रतियोगिता हेतु चयन

श्री विजय पुरम, 18 मार्च

द्वीपसमूह के उदीयमान टेबल टेनिस खिलाड़ियों का चयन 23 से 31 मार्च, 2026 तक गुजरात के गांधीधाम में आयोजित होने वाली 87वीं सब–जूनियर राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया गया है। चयनित खिलाड़ियों में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, स्वराज द्वीप के कुशल बैरागी (अंडर–15) एवं अक्षब मिस्त्री (अंडर–13) तथा नेवल चिल्ड्रन स्कूल, मिनी बे के जेसन इस्साक पलास्कर (अंडर–13) एवं जेसी इस्साक पलास्कर (अंडर–11 बालिका) शामिल हैं।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार टीम 19 मार्च, 2026 को श्री विजय पुरम से प्रस्थान कर इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेगी। अण्डमान तथा निकोबार राज्य टेबल टेनिस संघ की अध्यक्षा श्रीमती जोशना बाला एवं सचिव श्रीमती जेसी ने सभी खिलाड़ियों को चैंपियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु शुभकामनाएँ दी हैं।

विश्व सामाजिक न्याय दिवस पर जेएनआरएम में जागरूकता सह कार्यशाला संचालित

श्री विजय पुरम, 18 मार्च

विश्व सामाजिक न्याय दिवस के उपलक्ष्य में समग्र क्षेत्रीय केंद्र, कौशल विकास, पुनर्वास एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण (सीआरसी, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह) द्वारा यहां के जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय (जेएनआरएम) की गैलरी में "कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम (पोश अधिनियम, 2013)" तथा "दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016" विषयों पर जागरूकता सह कार्यशाला का आयोजन किया गया।

इस कार्यक्रम में 125 विद्यार्थियों ने संकाय सदस्यों के साथ उत्साहपूर्वक भागीदारी की, जिससे समानता, गरिमा एवं समावेशन को बढ़ावा देने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण पहल सिद्ध हुई। श्रीमती सुमितामोल एस, निदेशक, सीआरसी अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह ने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण हेतु सीआरसी की गतिविधियों एवं पहलों का अवलोकन प्रस्तुत किया। उन्होंने सामाजिक न्याय शपथ भी दिलाई, जिसे सभी 125 विद्यार्थियों ने गंभीरता के साथ ग्रहण करते हुए समानता, भेदभाव रहित व्यवहार एवं समावेशी दृष्टिकोण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

कार्यक्रम का उद्घाटन डॉ. पर्ल देवदास, प्राचार्या, जेएनआरएम द्वारा किया गया, जिन्होंने सुरक्षित, सम्मानजनक एवं समावेशी समाज के निर्माण में विद्यार्थियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल

दिया। तकनीकी सत्र अत्यंत ज्ञानवर्धक एवं रोचक रहे। श्रीमती रुबिना सिद्दीकी, अध्यक्ष, राइट्स फॉर ऑल एवं पोश अधिनियम की मास्टर ट्रेनर ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम (पोश अधिनियम, 2013) विषय पर विशेषज्ञ व्याख्यान देते हुए विद्यार्थियों को कार्यस्थल की नैतिकता, अधिकारों एवं कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूक किया।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार श्री वेंकट रमणा, सहायक, सीआरसी, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह ने अपने स्वागत संबोधन में युवाओं के बीच सामाजिक न्याय एवं समावेशी ज़िम्मेदारी के महत्व को रेखांकित किया। इसके पश्चात श्रीमती सरन्या आर.के., पुनर्वास अधिकारी, सीआरसी, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह द्वारा "दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (आरपीडब्ल्यूडी एक्ट)" पर विस्तृत सत्र प्रस्तुत किया गया।

अंतर–विद्यालय अंडर–17 फुटबॉल नॉकआउट टूर्नामेंट में छात्रों का शानदार प्रदर्शन

श्री विजय पुरम, 18 मार्च

आगामी 65वें सुब्रतो कप अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट के संदर्भ में उप शिक्षा कार्यालय, दक्षिण अण्डमान द्वारा आज भातूबस्ती स्कूल मैदान में आयोजित अंडर–17 (बालक) अंतर–विद्यालय फुटबॉल नॉकआउट टूर्नामेंट–2026 में दक्षिण अण्डमान अंचल के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने उत्साह, कौशल और टीम भावना का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार अंडर–17 बालक वर्ग में मंगलूटान स्कूल ने जीडीएमएस (एस) को 02–01 गोल (टाई ब्रेकर) से पराजित किया। आरबीवी स्कूल ने दिलानीपुर स्कूल को 03–00 गोल से हराया, जंगलीघाट स्कूल ने महात्मा गांधी इंटरनेशनल स्कूल को 01–00

गोल से परास्त किया तथा निर्मला स्कूल ने कालीकट स्कूल को 02–00 गोल से हराया।

फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद सभी

पृष्ठ 1 का शेष

अब तक इस कंट्रोल रूम को 3,305 कॉल और 6,324 ईमेल मिल चुके हैं, जिनमें से पिछले 24 घंटे में ही 125 कॉल और 449 ईमेल शामिल हैं। सरकार ने अब तक 472 से ज्यादा भारतीय नाविकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की है, जिनमें पिछले 24 घंटे में 25 लोग शामिल हैं।

भारत का समुद्री क्षेत्र फिलहाल सामान्य रूप से काम कर रहा है, और किसी भी पोर्ट पर भीड़ या रुकावट की कोई समस्या नहीं है। गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के मरीन बोर्ड्स ने भी इसकी पुष्टि की है। पोर्ट्स पर जहाजों की आवाजाही और कार्गो ऑपरेशन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। अतिरिक्त स्टोरेज की भी व्यवस्था की गई है, जिसमें विशाखापत्तनम पोर्ट अथॉरिटी में करीब 2,260 वर्ग मीटर अतिरिक्त जगह बनाई गई है। वहीं जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी (जेएनपीए) में स्थिति सामान्य है और फंसे हुए कंटेनरों की संख्या 1,000 से घटकर करीब 770 रह गई है।

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय वेस्ट एशिया की स्थिति को देखते हुए शिपिंग मूवमेंट, पोर्ट ऑपरेशन, नाविकों की सुरक्षा और समुद्री व्यापार की निरंतरता पर लगातार नजर बनाए हुए है। इस बीच, भारत और मध्य–पूर्व के बीच हवाई सेवाएं भी धीरे–धीरे सामान्य हो रही हैं। संयुक्त अरब अमीरात में 17 मार्च को करीब 70 लाइट्स संचालित हुईं और आज करीब 75 लाइट्स के संचालन की उम्मीद है। 5 मार्च 2026 से रोजाना 50 से ज्यादा लाइट्स चल रही हैं, जिससे कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है।

इसके अलावा सऊदी अरब और ओमान से भारत के लिए लाइट्स लगातार चल रही हैं। कतर का एयरस्पेस आंशिक रूप से खुला है, जहां मंगलवार को 5 लाइट्स चलीं और बुधवार से भारत के 9 शहरों के लिए सेवाएं शुरू की गई हैं। हालांकि, कुवैत का एयरस्पेस 28 फरवरी से बंद है। सऊदी अरब के अल कैसुमा हवाई अड्डे से जजीरा एयरवेज की विशेष गैर–निर्धारित उड़ानों के संचालन की उम्मीद है।

अण्डमान कॉलेज में डिजिटल प्रौद्योगिकी हेतु अतिथि संकाय के लिए वॉक–इन–इंटरव्यू

श्री विजय पुरम, 18 मार्च

अण्डमान कॉलेज (एनकॉल) ने शैक्षणिक सत्र 2025–2026 के लिए "आवश्यकतानुसार" आधार पर डिजिटल प्रौद्योगिकी (वैल्यू एडेड कोर्स) हेतु अतिथि संकाय के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र अभ्यर्थियों को वॉक–इन–इंटरव्यू में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया है। अतिथि प्राध्यापक/संसाधन व्यक्ति को यूजीसी मानदंडों के अनुसार प्रति व्याख्यान 1,500 रुपये का मानदेय दिया जाएगा, जो अधिकतम 50,000 रुपये प्रति माह तक सीमित होगा। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी तथा संबंधित विषय में शिक्षण कार्यभार की आवश्यकता पर निर्भर करेगी।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार विस्तृत सूचना, आवेदन प्रपत्र एवं स्व–मूल्यांकन प्रपत्र महाविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट https://ancol.andamannicobar.gov.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थियों को 23 मार्च, 2026 को सुबह 10.30 बजे निर्धारित स्थान पर विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र, स्व–मूल्यांकन प्रपत्र, संबंधित दस्तावेज़ों की स्वप्रमाणित प्रतियां एवं मूल प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करने होंगे।

सूचना, प्रचार और पर्यटन निदेशालय द्वारा प्रकाशित तथा प्रबन्धक, राजकीय मुद्रणालय द्वारा मुद्रित, वितरण तथा विज्ञापन के लिए फोन–229465, प्रधान सम्पादक (प्रभारी) पी. कैरल डी. सोणी
e-mail:dweepsamachar@gmail.com

टीकों की शक्ति से मजबूत होता भारत का स्वास्थ्य तंत्र

नई दिल्ली, 18 मार्च।

टीके लगाकर और इसके माध्यम से बीमारियों के संपर्क में आने के जोखिम को घटाकर प्रति वर्ष करोड़ों लोगों की जान बचाई जाती है। यह बीमारियों से बचाव के लिए लोगों में प्राकृतिक सुरक्षा तंत्र का निर्माण करते हैं।

भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार पर टीकों का जबरदस्त प्रभाव पड़ा है। भारत में पोलियो के अतिरिक्त टीकों ने चेचक, याव्स तथा माताओं और नवजात शिशुओं में टेटनस का उन्मूलन कर दिया है। उनके उपयोग ने बाल मृत्यु दर, खसरा–रूबेला और तपेदिक को घटा दिया है। कोविड–19 के दौरान विश्व की फार्मेसी के रूप में भारत ने 200 करोड़ से अधिक कोविड–19 वैक्सीन की खुराक की आपूर्ति की जिसमें भारत में निर्मित और स्वदेशी रूप से विकसित तथा लाइसेंस प्राप्त टीके शामिल हैं। 2026 में भारत सरकार ने सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए 14 वर्ष की आयु की लड़कियों के लिए राष्ट्रव्यापी एचपीवी टीकाकरण अभियान और स्वदेश में निर्मित टेटनस–डिप्थीरिया (टीडी) टीका लगाने का कार्यक्रम शुरू किया।

भारत में चलाए जा रहे सशक्त सबके लिए टीकाकरण कार्यक्रम (यूआईपी), सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित स्वास्थ्य केंद्रों, कर्मियों और कोल्ड–चेन अवसंरचना के व्यापक नेटवर्क तथा शक्तिशाली डिजिटल नेटवर्क के सार्थक परिणाम मिले हैं।

भारत में पूर्ण टीकाकरण कवरेज 2015 में 62 प्रतिशत था जो जनवरी 2026 तक बढ़कर 98.4 प्रतिशत हो गया है। देश की कुल जनसंख्या में ऐसे बच्चों का प्रतिशत 2023 के 0.11 प्रतिशत से घटकर 2024 में 0.06 प्रतिशत हो गया है जिन्हें टीके की खुराक नहीं लगी। भारत में टीकाकरण को प्राथमिकता देने का लंबा इतिहास रहा है और देश में सबके लिए टीकाकरण कार्यक्रम के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य को और बेहतर बनाने के लिए उच्च टीकाकरण दरों पर बल देना जारी रखा गया है।

भारत में प्रति वर्ष 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 1995 में शुरू किए गए पल्स पोलियो कार्यक्रम के अंतर्गत नागरिकों को उसी वर्ष दी गई ओरल पोलियो टीके की पहली खुराक के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।

1995 में शुरू किए गए इस कार्यक्रम ने भारत में पोलियो का सफलतापूर्वक उन्मूलन कर दिया। भारत में इससे पीड़ित अंतिम रोगी 13 जनवरी, 2011 को पश्चिम बंगाल के हावड़ा में पाया गया था।

सबके लिए टीकाकरण कार्यक्रम

अपने बच्चों को पैदा होने पर माताएं रोगनिरोधी एंटीबॉडी प्रदान करती हैं। हालांकि, गर्भावस्था और स्तनपान के माध्यम से मां से बच्चे में स्थानांतरित होने वाले ये एंटीबॉडी केवल नवजात शिशु के जीवन के प्रारंभिक कुछ महीनों के लिए रोगों से बचाव और सुरक्षा प्रदान करते हैं।

शिशुओं और बच्चों को रोगाणुओं–कीटाणुओं और यहां तक कि जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए टीके महत्वपूर्ण हैं। बीमारियों के संपर्क में आने से पहले ही आदर्श रूप से जीवन के प्रारंभिक 12 से 18 महीनों के भीतर ही बच्चों को टीके देना सबसे अच्छा होता है।

1985 में शुरू किए गए और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से चलाए जा रहे सबके लिए टीकाकरण कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों और गर्भवती महिलाओं को विभिन्न बीमारियों से बचाव के लिए निःशुल्क टीके लगाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रति वर्ष लगभग 2.9 करोड़ गर्भवती महिलाओं और 2.54 करोड़ नवजात शिशुओं को टीके लगाए जाते हैं।

सबके लिए टीकाकरण कार्यक्रम (यूआईपी) के उद्देश्य हैं:

टीकाकरण का दायरा बढ़ाना, सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना, स्वास्थ्य सुविधा स्तर के अनुरूप विश्वसनीय कोल्ड चेन प्रणाली की स्थापना, प्रदर्शन की निगरानी, वैक्सीन उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना हैं। सबके लिए टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत नवजात शिशुओं, बच्चों, किशोरों और गर्भवती महिलाओं को 12 बीमारियों से बचाव के लिए टीके लगाए जाते हैं। जापानी इन्सेफलाइटिस का टीका केवल विशेष क्षेत्रों में प्रभावित जिलों के लोगों को प्रदान किया जाता है और बाकी राष्ट्रीय स्तर पर लगाए जाते हैं।

पिछले एक दशक में इस कार्यक्रम में विभिन्न नए टीके जोड़े गए जिनमें शामिल हैं:– निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन (आईपीवी) (2015), रोटावायरस वैक्सीन (आरवीवी) (2016), खसरा–रूबेला (एमआर) वैक्सीन (2017) और न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन (पीसीवी) (2017)।

सबके लिए टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत दिए जाने वाले टीके हैं:

बैसिलस कैलमेट–गुएरिन (बीसीजी)
डिप्थीरिया, पर्टुसिस (काली खांसी) और टेटनस (डीपीटी)
टेटनस और वयस्क डिप्थीरिया (टीडी)
बाई वैलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन (बीओपीवी)
खसरा–रूबेला (एमआर) का टीका
हेपेटाइटिस बी (हेप बी)
पेंटावैलेंट: डीपीटी + हेपेटाइटिस बी + हीमोफिलस इन्लुएंजा टाइप बी (डीपीटी + हेप बी + हिब)
रोटावायरस वैक्सीन (आरवीवी)
न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन (पीसीवी)
जापानी इंसेफलाइटिस (जेई) वैक्सीन, ये टीके जानलेवा बीमारियों से बचाते हैं।

1 क्षय रोग (बचपन में गंभीर रूप): फेफड़ों को प्रभावित करने वाला जीवाणु संक्रमण, मस्तिष्क और कई अंगों में फैल सकता है,
2 डिप्थीरिया: गले को प्रभावित करने वाला जीवाणु संक्रमण, हृदय और नसों को नुकसान पहुंचा सकता है,
3 पर्टुसिस (काली खांसी): अत्यधिक संक्रामक खांसी की बीमारी, शिशुओं के लिए खतरनाक
4 टेटनस: दूषित घावों से जीवाणु संक्रमण जिससे मांसपेशियों में अकड़न होती है,
5 पोलियो: वायरल संक्रमण जो तंत्रिका तंत्र पर आक्रमण करता है, स्थायी पक्षाघात या मृत्यु का कारण बन सकता है,
6 खसरा: अत्यधिक संक्रामक वायरल रोग, बुखार और दाने का कारण बनता है,
7 रूबेला: बुखार और दाने के साथ हल्की वायरल बीमारी, खांसने और छींकने से फैलती है,
8 हेपेटाइटिस बी: लीवर का वायरल संक्रमण जो पुराना हो सकता है और लीवर को नुकसान पहुंचा सकता है,
9 मेनिनजाइटिस और निमोनिया (एचआईबी): मेनिनजाइटिस – मस्तिष्क और रीढ़ की

हड्डी के आसपास की झिल्लियों का संक्रमण और सूजन निमोनिया– फेफड़ों का संक्रमण और सूजन,
10 रोटावायरस डायरिया: वायरल संक्रमण के कारण शिशुओं में गंभीर दस्त,
11 न्यूमोकोकल निमोनिया: फेफड़ों में जीवाणु संक्रमण के कारण बुखार और सांस लेने में कठिनाई होती है,
12 जापानी इन्सेफलाइटिस: मच्छर जनित वायरल रोग पैदा करने वाली मस्तिष्क की सूजन
राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी,

जानलेवा बीमारियों से सुरक्षा के लिए समय पर टीके लगवाना महत्वपूर्ण है। यहां गर्भवती महिलाओं, शिशुओं और बच्चों के लिए सबके लिए टीकाकरण (यूआईपी) के अंतर्गत निर्धारित सारणी दी गई है।

गर्भवती महिलाएं

- टीडी –1 पहली एंटीनेटल विज़िट के दौरान जितनी जल्दी हो सके
- टीडी –2 पहले टीडी शॉट के 4 हते बाद
- टीडी –बूस्टर अगर पिछले 3 सालों में पिछली प्रेग्नेंसी में दो टीडी डोज़ पहले ही लग चुकी हों

व सभी डोज़ आमतौर पर 36 हते से पहले दी जाती हैं . लेकिन लेबर के दौरान भी, अगर छूट जाए तो भी दी जाती हैं

शिशु और बच्चे

जन्म के समय
हेप बी, बीओपीवी, बीसीजी
पहले जन्मदिन तक
बीओपीवी की 3 खुराक, रोटावायरस वैक्सीन की 3 खुराक, पेंटावैलेंट की 3 खुराक, आंशिक आईपीवी की 3 खुराक, पीसीवी की 3 खुराक, एमआर वैक्सीन की पहली खुराक, जेई वैक्सीन की पहली खुराक (जहां लागू हो)
दूसरे जन्मदिन तक
एमआर वैक्सीन की 2 खुराक, डीपीटी बूस्टर की पहली खुराक, बीओपीवी बूस्टर की 1 खुराक, वीई वैक्सीन की दूसरी खुराक (जहां लागू हो)
पांचवें जन्मदिन के बाद
5 साल की उम्र में डीपीटी बूस्टर की दूसरी खुराक, 10 साल की उम्र में टीडी वैक्सीन की 1 खुराक, 16 साल की उम्र में टीडी वैक्सीन की 1 खुराक, हाल ही में लॉन्च किए गए टीके और कार्यक्रम

इस विस्तार का सबसे ताज़ा अध्याय सबसे महत्वाकांक्षी भी है। इसमें 2026 की शुरूआत में हुए दो ऐतिहासिक लॉन्च शामिल हैं जो सबके लिए टीकाकरण कार्यक्रम की पहुंच का विस्तार करते हैं।

स्वदेशी टेटनस–डिप्थीरिया (टीडी) टीका लॉन्च (2026)

21 फरवरी 2026 को स्वदेशी रूप से निर्मित टेटनस और एडल्ट डिप्थीरिया (टीडी) टीका लॉन्च किया गया था। इस टीके का उत्पादन केंद्रीय अनुसंधान संस्थान (सीआरआई), कसौली में किया जाता है। अप्रैल 2026 तक सबके लिए टीकाकरण कार्यक्रम (यूआईपी) के लिए इस टीके की लगभग 55 लाख खुराक की आपूर्ति की जाएगी।

भारत की घरेलू टीका निर्माण क्षमता ही इस पूरी व्यवस्था का आधार है। भारत विश्व के सबसे बड़े टीका उत्पादक के तौर पर विश्व भर में टीके की लगभग 60 प्रतिशत आपूर्ति करता है। वहीं, स्वदेशी रूप से निर्मित टीडी टीके को लॉन्च किया जाना इस क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता की अभिव्यक्ति है।

राष्ट्रव्यापी एचपीवी टीकाकरण अभियान (2026)

28 फरवरी 2026 को राष्ट्रव्यापी ह्यूमन पैपिलोमावायरस (एचपीवी) टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था। इस अभियान की शुरूआत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राजस्थान के अजमेर से की थी। इसका लक्ष्य 14 साल की लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाना है। इसके अंतर्गत संपूर्ण भारत में लगभग 1.15 करोड़ लड़कियों को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मुफ्त टीका लगाए जाने की उम्मीद है।

मिशन इंद्रधनुष

सरकार ने 2015 में मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम शुरू किया जिसका लक्ष्य उन बच्चों और गर्भवती महिलाओं तक पहुंचना है जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है या जिन्हें आंशिक रूप से टीका लगाया गया है। इसके बाद मंत्रालयों के बीच अधिक आपसी संपर्क के साथ गहन मिशन इंद्रधनुष मिशन (शहरी क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देने के साथ) शुरु किया गया । इन मिशनों का उद्देश्य नियमित टीकाकरण सेवाओं को सशक्त बना कर और दुर्गम आबादी को लक्षित करके सबके लिए टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 90 प्रतिशत से अधिक पूर्ण टीकाकरण कवरेज प्राप्त करना है।

2023 तक मिशन इंद्रधनुष के 12 चरण आयोजित किए जा चुके हैं जिसमें 765 जिलों में 5.46 करोड़ शिशुओं और 1.32 करोड़ गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया गया। यूआईपी के कार्यान्वयन में सहयोग के लिए बुनियादी ढांचा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और कार्यकर्ता।

टीके कहां लगाए जाते हैं?

यूआईपी टीके सभी लाभार्थियों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सरकारी अस्पतालों जैसे निर्धारित स्थलों पर, उपकेन्द्रों पर और आंगनवाड़ी केन्द्रों अथवा गांवों के भीतर अन्य चिन्हित स्थानों पर आयोजित आउटरीच सत्रों के माध्यम से निशुल्क लगाए जाते हैं। वर्ष 2005 से यूआईपी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत है। इस मिशन के अंतर्गत शहरी मलिन बस्तियों में भी यूआईपी को लागू किया गया है।

अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कार्यकर्ता – आशा (मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता), आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (एडब्ल्यूडब्ल्यू) और लिंक कार्यकर्ता – लाभार्थियों को टीकाकरण के सत्र स्थलों पर लाने और यह सुनिश्चित करने में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं कि कोई भी बच्चा या गर्भवती महिला छूट न जाए।

आदर्श टीकाकरण केंद्र

भारत सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदर्श टीकाकरण केंद्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। वे उत्तर प्रदेश, बिहार और चंडीगढ़ और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में पहले से ही काम कर रहे हैं।

कोल्ड–चेन नेटवर्क

टीके जब तक निर्मित होते हैं तब से टीकाकरण के क्षण तक उन्हें लगातार सीमित तापमान सीमा के भीतर रखा जाना चाहिए। बहुत अधिक या बहुत कम तापमान टीके की शक्ति (बीमारी से बचाने की क्षमता) के क्षय का कारण बन सकता है और एक बार क्षय हो जाने के बाद उस शक्ति को पुनः प्राप्त या बहाल नहीं किया जा सकता है। इन निर्धारित शर्तों में टीकों के भंडारण और परिवहन की प्रणाली को कोल्ड चेन सिस्टम कहा जाता है। यह व्यापक वैक्सीन आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा है जिसे टीकाकरण कवरेज और पहुंच सुनिश्चित करने के लिए निर्बाध और कुशल होना चाहिए।

भारत की वैक्सीन कोल्ड चेन विश्व में सबसे बड़ी ऐसी शृंखलाओं में से एक है– यह राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी चिकित्सा आपूर्ति डिपो से लेकर जिलों में निम्न स्तरों पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक, लगभग 30,000 कोल्ड चेन पॉइंट्स के रूप में फैली हुई है। अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं में यह भंडारण व्यवस्था 1.06 लाख से अधिक आइस–लाइन रेफ्रिजरेटर और डीप फ्रीजर और टीके के थोक भंडारण के लिए 432 वॉक–इन कूलर और वॉक–इन फ्रीजर से सुसज्जित हैं। इस नेटवर्क में यह सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वार्षिक 1.3 करोड़ से अधिक टीकाकरण सत्रों का आयोजन करने के दौरान प्रत्येक बिंदु पर तापमान में बदलाव या उतार–चढ़ाव न हो ताकि टीके उपयुक्त स्थिति में अंतिम लाभार्थी तक पहुंचें।

इस विशाल बुनियादी ढांचे को डिजिटल और सशक्त बनाने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय मजबूत आईटी बुनियादी ढांचे और प्रशिक्षित पेशेवरों से लैस एक अत्याधुनिक सॉटवेयर प्लेटफॉर्म इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क (ईवीआईएन) का उपयोग करता है जो देश भर में कई स्थानों पर वास्तविक समय में टीके के भंडार के स्तर और भंडारण के तापमान पर नज़र रखता है। ईवीआईएन ने देश भर में सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में विस्तार किया है। यह प्लेटफॉर्म कोविड –19 महामारी के दौरान महत्वपूर्ण साबित हुआ जिससे कम समय में रिकॉर्ड संख्या में लोगों का टीकाकरण संभव हो सका।

डिजिटल पहल

भारत की टीकाकरण प्रबंधन प्रणाली को पंजीकरण, टीका लगवाने के लिए समय लेने और तय करने, वैक्सीन ट्रैकिंग और वास्तविक समय में निगरानी के लिए उपयुक्त प्लेटफॉर्म के साथ सशक्त डिजिटल अनुकूल परिवेश के माध्यम से उन्नत किया गया है।

यू–विन

यू–विन एक डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऐप है जो लोगों को उनके निवास के पास टीकाकरण केंद्र की तलाश करने, स्वास्थ्य सुविधाओं में टीकाकरण के लिए समय निर्धारण के प्रबंधन और टीकाकरण का रिकॉर्ड बरकरार रखने में मदद करता है। इसमें एक उपयोगकर्ता एक मोबाइल नंबर पर अधिकतम 10 लोगों का पंजीकरण कर सकता है, जिसमें नागरिक/अभिभावक, गर्भवती महिलाएं, शिशु (0–1 वर्ष), बच्चे (1–7 वर्ष) और किशोर (7–19 वर्ष) शामिल हैं। यू–विन को अक्टूबर 2024 में लॉन्च किया गया था और यह अंग्रेजी सहित 12 भाषाओं में उपलब्ध है।

कोविन

यू–विन की तरह कोविन स्वास्थ्य और अन्य केंद्रों पर कोविड–19 टीकाकरण पंजीकरण और टीके लगवाने के लिए समय लेने तथा रिकॉर्ड के प्रबंधन के लिए बनाया गया डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसे 16 जनवरी 2021 को लॉन्च किया गया था और तब से इसके माध्यम से टीकों की 220 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं जिनमें से केवल 56.28 लाख कोविन के माध्यम से नहीं दी गई हैं।

प्रभाव

भारत में शिशु और गर्भवती महिलाओं की उत्तरजीविता दर में हुए व्यापक लाभ के पीछे पोषण, स्वच्छता, मातृ देखभाल और स्वास्थ्य देखभाल पहुंच में सुधार जैसे कई कारकों के साथ–साथ टीकाकरण भी एक है। बेहतर पोषित, बेहतर टीकाकरण वाली महिलाओं को गर्भावस्था और प्रसव के दौरान कम खतरे का सामना करना पड़ता है जबकि टीके देने वाली मजबूत स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली भी कुशल जन्म परिचारकों और आपातकालीन प्रसूति देखभाल तक पहुंच का विस्तार करती है जिससे मातृ मृत्यु दर कम हो जाती है।

नए टीके – रोटावायरस, पीसीवी, और खसरा–रूबेला – ने सीधे बाल मृत्यु के प्रमुख संक्रामक कारणों को लक्षित किया है। देश की जनसंख्या के मुकाबले उन बच्चों का प्रतिशत 2023 में 0.11प्रतिशत से घटकर 2024 में 0.06 प्रतिशत हो गया है जिन्हें टीके की एक भी खुराक नहीं लगी– इस उपलब्धि को बाल मृत्यु दर अनुमान के लिए संयुक्त राष्ट्र के अंतर–एजेंसी समूह (2024) ने स्वीकार किया है और भारत को बाल स्वास्थ्य में वैश्विक उदाहरण के रूप में स्थापित किया है।

टीकाकरण अभियान सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा से कहीं अधिक परिवारों पर बीमारी के वित्तीय बोझ को कम करते हैं, बच्चों को स्वस्थ रखते हैं और उन्हें पूर्ण, अधिक सार्थक जीवन जीने की अनुमति देते हैं। ये लाभ पीढ़ियों तक फैले हुए हैंरू एक स्वस्थ बच्चा एक स्वस्थ वयस्क बन जाता है और एक स्वस्थ जनसंख्या कार्यबल में अधिक उत्पादक योगदान देती है जिससे व्यापक सामाजिक और आर्थिक प्रगति होती है।

1977 में चेचक उन्मूलन से लेकर पोलियो और नवजात शिशुओं में टेटनस को खत्म करने, 200 करोड़ कोविड–19 खुराक देने और अब खसरा–रूबेला उन्मूलन का प्रयास करने तक– भारत की टीकाकरण यात्रा नई–नई ऐतिहासिक उपलब्धियों में से एक है, यह बात प्रमाणित हो चुकी है।

ई–निविदा सूचना

कार्यपालक अभियंता, पंचायती राज संस्थान, दक्षिण अण्डमान मण्डल–।, श्री विजय पुरम, दक्षिण अण्डमान, प्रधान, ग्राम पंचायत, सिप्पीघाट की ओर से, निम्नलिखित कार्यो के लिए उचित श्रेणी के योग्य व अनुभवी ठेकेदारो से मुहरबंद मद दर (के.लो.नि.वि.–8 के प्रपत्र के रूप में) आमंत्रित करते है।

एन. आई. टी. संख्या : क.अ./पी आर आई/एस ए डी–।/आर आर/2025–26/206

कार्य का नाम : सिप्पीघाट, ग्राम पंचायत के अंर्तगत सिप्पीघाट 02 में एटीआर मुख्य सड़क के पास श्री. किरपाल के घर से प्रेम सिंह के घर तक जिसमें मौजूदा फुटपाथ को जोड़ने वाली हैंड रेलिंग के साथ सी सी फुटपाथ की मरम्मत और रखरखाव।

अनुमानित लागत : रु. 11,07,936/–, धरोहर राशि : रु. 22,159/–, कार्य समाप्ति की अवधि : (04) चार माह।

निविदा शुल्क : रु. 500/–, बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि : 25/03/2026 के सायं 3.00 बजे तक।

निविदा प्रपत्र और अन्य विवरण वेबसाइट https://eprocure.andamannicobar.gov.in से प्राप्त किए जा सकते हैं।

टेंडर आई डी : 2026_RDPRI_22363_1

कार्यपालक अभियंता,
पंचायती राज संस्थान, दक्षिण अण्डमान मण्डल–।,
जंगलीघाट, श्री विजय पुरम, दक्षिण अण्डमान

ई–निविदा सूचना

कार्यपालक अभियंता, पंचायती राज संस्थान, दक्षिण अण्डमान मण्डल–।, श्री विजय पुरम, दक्षिण अण्डमान, प्रमुख, पंचायत समिति, फरारगंज की ओर से, निम्नलिखित कार्यों के लिए उचित श्रेणी के योग्य व अनुभवी ठेकेदारों से मुहरबंद मद दर (के.लो.नि.वि.–8 के प्रपत्र) के रूप में आमंत्रित करते है।

एन. आई. टी. संख्या : क.अ./पी आर आई/एस ए डी–।/आर आर(सीसीए)/2025–26/215

कार्य का नाम : वृंदाबन ग्राम पंचायत के अंतर्गत समिति द्वारा वृंदाबन में मुख्य सड़क से मुरुगन मंदिर होते हुए गांव की सड़क तक सीसी रोड का निर्माण कार्य ।

अनुमानित लागत : रु. 31,93,939/–, धरोहर राशि : रु. 63,879/–, कार्य समाप्ति की अवधि : (06) छह माह।

निविदा शुल्क : रु. 500/–, बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि : 25/03/2026 के सायं 3.00 बजे तक। निविदा प्रपत्र और अन्य विवरण वेबसाइट https://eprocure.andamannicobar.gov.in से प्राप्त किए जा सकते हैं।

टेंडर आई डी: 2026_RDPRI_22401_1

कार्यपालक अभियंता,
पंचायती राज संस्थान, दक्षिण अण्डमान मण्डल–।,
जंगलीघाट, श्री विजय पुरम, दक्षिण अण्डमान

ई–निविदा सूचना

F.No. Proc-201/2/2023-Mg-Tourism-ANIIDCO_AN/6310

दिनांक 17.03.2026

हॉर्नबिल नेस्ट रिसॉर्ट, श्री विजय पुरम के लिए वार्षिक आधार पर टैंकर द्वारा पीने के पानी की आपूर्ति हेतु ऑनलाइन ई–निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा के नियम और शर्तें युक्त दस्तावेज वेबसाइट https://eprocure.andamannicobar.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है अथवा वरिष्ठ प्रबंधक (पर्यटन), विकास भवन, श्री विजय पुरम से सभी कार्य दिवसों के दौरान दिनांक 08.04.2026 के सायं 5.00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।

निविदा ऑनलाइन https://eprocure.andamannicobar.gov.in पर 09/04/2026 को पूर्वाहन 11.00 बजे तक भरी जानी चाहिए और दस्तावेजों को सीलबंद लिफाफे में विकास भवन, श्री विजय पुरम में रखे गए निविदा पेटी में 09/04/2026 को दोपहर 12.00 बजे तक जमा किया जाना चाहिए। तकनीकी बोली उसी दिन सायं 4.00 बजे निविदाकर्ताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जाएगी, यदि निविदा खोलने के समय कोई उपस्थित हो।

महाप्रबंधक (पर्यटन), अनिडको को बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी निविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

महाप्रबंधक (पर्यटन), अनिडको

ऑरलियन्स मास्टर्स में आकर्षी कश्यप ने दोनों क्वालीफाइंग मैच जीते

नई दिल्ली, 18 मार्च।

ऑरलियन्स मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की आकर्षी कश्यप ने अपने दोनों क्वालीफाइंग मैच जीतकर के महिला सिंगल्स के मुख्य ड्रॉ में प्रवेश किया। फ्रांस के पैलेस डे स्पोर्ट्स में खेले गए टूर्नामेंट में, आकर्षी ने महिला सिंगल्स रैंकिंग में हमवतन, श्रीयांशी वलीशेट्टी को हराकर अपने अभियान की शुरुआत की।

देश में बढ़ती गर्मी के मद्देनजर एन.सी.डी.सी. ने नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया

नई दिल्ली, 18 मार्च।

देश में बढ़ती गर्मी के मद्देनजर राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र एन.सी.डी.सी. ने नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है। एन.सी.डी.सी ने सलाह दी है कि तेज गर्मी के दौरान लू लगने से बचने के लिए खूब पानी पिएं और भारी काम करने से बचें। इसके साथ ही हल्के रंग के कपड़े पहनें। एनसीडीसी ने कहा कि लू से पीड़ित व्यक्ति को प्राथमिक उपचार के दौरान ठंडी जगह पर लिटाया जाना चाहिए। पीड़ित की हालत में सुधार होने पर उसे ठंडी सिकाई करनी चाहिए और थोड़ी–थोड़ी देर में ठंडा पानी और नमीयुक्त खाद्य पदार्थ पिलाने चाहिए।

पार्सलों के वितरण में सुधार लाने के लिए मेल पार्सल ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट शुरू: संचार मंत्री

नई दिल्ली, 18 मार्च।

संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि डाक विभाग ने पार्सलों के वितरण में सुधार लाने के लिए मेल पार्सल ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट शुरू किया है। लोकसभा में आज पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री सिंधिया ने कहा कि इस पहल के तहत, पार्सल नेटवर्क और वितरण केंद्रों को युक्तिसंगत बनाया गया है और अखिल भारतीय सड़क परिवहन नेटवर्क को चालू किया गया है।

श्री सिंधिया ने कहा कि विभाग ने पिछले तीन वर्षों में देश के सभी जिलों में डाकघरों, मेल और पार्सल प्रसंस्करण केंद्रों के बुनियादी ढांचे को उन्नत बनाने के लिए विभिन्न पहलें की हैं। इन पहलों से पार्सल संभालने की क्षमता में वृद्धि हुई है। संचार मंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2020–21 में नौ करोड़ 72 लाख से बढ़कर वित्त वर्ष 2024–25 में 14 करोड़ पांच लाख पार्सल वितरित किए गए।

आईओएस सागर पहल, भारतीय नौसेना का 16 देशों के साथ समुद्री साझेदारी को मजबूत करने की पहल

नई दिल्ली, 18 मार्च।

भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में सहयोगात्मक समुद्री सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहरा रही है। ऐसा करते हुए नौसेना ने 'आईओएस सागर' के दूसरे संस्करण की शुरुआत कर दी है। दरअसल भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किया गया 'आईओएस सागर' एक विशेष ऑपरेशनल कार्यक्रम है। इसका मूल उद्देश्य मित्र राष्ट्रों के नौसैनिकों को भारतीय नौसेना के जहाज पर एक साथ प्रशिक्षण और समुद्री अनुभव प्रदान करना है। यह कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है।

नौसेना ने 16 मार्च से इसकी शुरुआत कर दी है। भारतीय नौसेना के मुताबिक इस पहल के तहत विभिन्न देशों के इन अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागियों को जहाज पर होने वाली गतिविधियों और पेशेवर प्रशिक्षण में शामिल किया जाता है। इससे अलग–अलग देशों के नौसैनिकों के बीच आपसी तालमेल, सहयोग और समुद्री अभियानों की समझ को बढ़ावा मिलता है। प्रारंभ किए गए इस संस्करण में 16 मित्र देशों के नौसैनिक भाग ले रहे हैं।

कार्यक्रम की एक महत्वपूर्ण व मूल शुरुआत केरल के कोच्चि स्थित नौसेना प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में पेशेवर प्रशिक्षण सत्रों से होगी। यहां विभिन्न देशों की नौसेनाओं से आए प्रतिभागियों को नौसैनिक संचालन, समुद्री कौशल और समुद्री सुरक्षा से जुड़े प्रमुख पहलुओं की जानकारी दी जाएगी। इसके बाद प्रतिभागी भारतीय नौसेना के एक जहाज पर तैनात होकर समुद्र में संयुक्त रूप से संचालन गतिविधियों में भाग लेंगे। इस दौरान वे भारतीय नौसेना के साथ मिलकर व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करेंगे।

यात्रा के दौरान नौसेना का यह समुद्री जहाज विभिन्न बंदरगाहों का दौरा करेगा। इन समुद्री यात्राओं में क्षेत्रीय नौसेनाओं तथा समुद्री एजेंसियों के साथ संवाद स्थापित किया जाएगा। इन गतिविधियों का उद्देश्य पेशेवर संबंधों को मजबूत करना, श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों का आदान–प्रदान करना और साझा समुद्री चुनौतियों की गहन समझ विकसित करना है।

गौरतलब है कि इसी साल फरवरी में भारतीय नौसेना ने इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम की अध्यक्षता संभाली है। इसी के तहत इस संस्करण में हिंद महासागर क्षेत्र के 16 सदस्य देशों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। अब नौसेना की यह पहल भारत की दीर्घकालिक समुद्री सहयोग नीति को आगे बढ़ाती है।

यह पहल, क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास (सागर) संबंधी भारत सरकार के दृष्टिकोण को साकार करती है। साथ ही यह व्यापक महासागर (क्षेत्रों में सुरक्षा के लिए पारस्परिक और समग्र प्रगति) ढांचे को भी मजबूती देती है। नौसेना का मानना है कि यह पहल हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में भारत की सक्रिय भूमिका को और सुदृढ़ करती है।

पांच राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में हिंसा–मुक्त और प्रलोभन–मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने के लिए 25 लाख से अधिक अधिकारियों की तैनाती

नई दिल्ली, 18 मार्च

चुनाव आयोग ने 5 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में हिंसा–मुक्त और प्रलोभन–मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने के लिए 25 लाख से अधिक अधिकारियों को तैनात किया है।

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने 15 मार्च, 2026 को असम, केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की विधानसभाओं के लिए आम चुनाव और 6 राज्यों में उप चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया।

पांच राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव के विभिन्न चरणों को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए 25 लाख से अधिक चुनाव अधिकारियों को तैनात किया गया है। इन चुनावों में मतदान के पात्र मतदाताओं की कुल संख्या 17.4 करोड़ से अधिक है। इसका मतलब है कि लगभग हर 70 मतदाताओं पर 1 चुनाव अधिकारी तैनात है।

मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए कहा था कि अधिकारियों को पूर्ण निष्पक्षता के साथ कार्य करने का निर्देश दिया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चुनाव हिंसा–मुक्त और प्रलोभन–मुक्त हों और प्रत्येक मतदाता बिना किसी भय या पक्षपात के मतदान कर सके।

तैनात कर्मियों में लगभग 15 लाख मतदान कर्मी, 8.5 लाख सुरक्षा कर्मी, 40 हजार मतगणना कर्मी, 49 हजार सूक्ष्म पर्यवेक्षक, 21 हजार सेक्टर अधिकारी, मतगणना के लिए 15 हजार सूक्ष्म पर्यवेक्षक और अन्य अधिकारी शामिल हैं।

2.18 लाख से अधिक बीएलओ सहित जमीनी स्तर की चुनाव मशीनरी मतदाताओं के लिए फोन कॉल और ईसीआईएनईट ऐप पर बीएलओ को कॉल बुक करने की सुविधा के माध्यम से उपलब्ध है। डीईओ/आरओ स्तर पर किसी भी शिकायत/प्रश्न को दर्ज करने के लिए कॉल सेंटर नंबर +91 (एसटीडी कोड) 1950 भी उपलब्ध है।

तैनात किए गए सभी कर्मियों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 28ए के प्रावधानों के अनुसार चुनाव आयोग में प्रतिनियुक्ति पर माना जाएगा।

आम चुनाव और उपचुनावों के दौरान आयोग की निगरानी के लिए 832 विधानसभा क्षेत्रों में 1,111 केंद्रीय पर्यवेक्षकों को तैनात किया गया है। इनमें 557 सामान्य पर्यवेक्षक, 188 पुलिस पर्यवेक्षक और 366 व्यय पर्यवेक्षक शामिल हैं। तैनात किए गए अधिकांश केंद्रीय पर्यवेक्षक अपने–अपने निर्धारित केंद्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में पहुंच चुके हैं।

पर्यवेक्षक अपने संपर्क विवरण साझा करेंगे और उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों या उनके प्रतिनिधियों या जनता के किसी भी सदस्य से प्रतिदिन एक निर्दिष्ट समय पर मिलकर उनकी चुनाव संबंधी शिकायतों को सुनेंगे।

खाद्य मिलावट पर सख्ती: तीन साल में 5.18 लाख नमूनों की जांच, 88 हजार से ज्यादा जुर्माने

नई दिल्ली, 18 मार्च।

खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए देशभर में व्यापक स्तर पर निगरानी और कार्रवाई तेज की गई है। पिछले तीन वर्षों में लाखों नमूनों की जांच, हजारों मामलों में जुर्माना और दोष सिद्धि के जरिए इस दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं।

तीन वर्षों में व्यापक कार्रवाई

खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के तहत वर्ष 2022–23 से 2024–25 के बीच कुल 5,18,559 खाद्य नमूनों का विश्लेषण किया गया। इस दौरान 88,192 मामलों में जुर्माना लगाया गया, जबकि 3,614 मामलों में दोष सिद्ध हुए। इसके अलावा 1,161 लाइसेंस भी रद्द किए गए। दूध, घी, मसाले, शहद, पनीर समेत विभिन्न खाद्य उत्पादों की नियमित निगरानी, निरीक्षण और नमूनाकरण किया गया, ताकि उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा सके।

कानून और जिम्मेदारियां तय

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण को खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानक तय करने और सुरक्षित एवं पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत इसके कार्यान्वयन और प्रवर्तन की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझा है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में खाद्य सुरक्षा आयुक्त और खाद्य सुरक्षा अधिकारी जमीनी स्तर पर कानून के पालन को सुनिश्चित करते हैं।

जोखिम आधारित निरीक्षण प्रणाली लागू

एफएसएसएआई ने जोखिम आधारित निरीक्षण प्रणाली विकसित की है, जिसके तहत खाद्य व्यवसायों के जोखिम स्तर के आधार पर निरीक्षण की आवृत्ति तय की जाती है। उच्च जोखिम वाली श्रेणियों में शामिल खाद्य इकाइयों का हर वर्ष निरीक्षण किया जाता है। पिछले तीन वर्षों में इस प्रणाली के तहत 56,259 निरीक्षण किए गए।

बुनियादी ढांचे को मिला मजबूती

खाद्य सुरक्षा प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर रही है। इसमें लाइसेंसिंग और पंजीकरण व्यवस्था को मजबूत करना, नमूनों की जांच, उपभोक्ता शिकायत निवारण, अधिकारियों का प्रशिक्षण और प्रयोगशालाओं के लिए आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराना शामिल है। साथ ही "ईट राइट कैंपस" और "ईट राइट स्कूल" जैसे अभियानों के जरिए जागरूकता भी बढ़ाई जा रही है।

प्रयोगशालाओं और मोबाइल जांच का विस्तार

देश में खाद्य परीक्षण को मजबूत करने के लिए 252 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं और 24 रेफरल प्रयोगशालाओं को अधिसूचित किया गया है। इसके अलावा, "फूड सेटी ऑन व्हील्स" के रूप में मोबाइल प्रयोगशालाएं भी तैनात की गई हैं, जो मौके पर ही खाद्य पदार्थों की जांच करती हैं। वर्तमान में 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 305 ऐसी मोबाइल लैब्स काम कर रही हैं, जो मिलावट के खिलाफ त्वरित कार्रवाई में अहम भूमिका निभा रही हैं।

राज्यसभा में दी गई जानकारी

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने राज्यसभा में लिखित उत्तर के माध्यम से यह जानकारी दी।

भारतीय तटरक्षक बल को मिलेगी नई ताकत, नेक्स्ट जेनरेशन पोत निर्माण शुरू

नई दिल्ली, 18 मार्च।

देश की समुद्री सुरक्षा को और मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। भारतीय तटरक्षक बल के लिए नेक्स्ट जेनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स (ओपीवी) के निर्माण का समारोह 17 मार्च 2026 को आयोजित किया गया।

रत्नागिरी में आयोजित हुआ निर्माण समारोह

यह समारोह रत्नागिरी स्थित मेसर्स वाईएमपीएल में आयोजित किया गया, जहां ओपीवी श्रृंखला के दूसरे और तीसरे पोत (यार्ड 16402 और 16403) के निर्माण की औपचारिक शुरुआत हुई।

अत्याधुनिक तकनीक से लैस होंगे पोत

ये नेक्स्ट जेनरेशन पोत 5,000 समुद्री मील की रेंज और 23 समुद्री मील की अधिकतम गति हासिल करने में सक्षम होंगे। करीब 117 मीटर लंबे इन पोतों में 11 अधिकारियों और 110 जवानों के रहने की क्षमता होगी। इनमें एआई–आधारित पूर्वानुमानित रखरखाव प्रणाली, रिमोट पायलटेड ड्रोन, इंटीग्रेटेड ब्रिज सिस्टम और इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम जैसी आधुनिक तकनीकें शामिल होंगी।

आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी निर्माण

यह परियोजना मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) द्वारा 'बाय (इंडियन–आईडीडीएम)' श्रेणी के तहत स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित की जा रही है। छह नेक्स्ट जेनरेशन ओपीवी के निर्माण का अनुबंध 20 दिसंबर 2023 को संपन्न हुआ था।

समुद्री सुरक्षा में होगा बड़ा इजाफा

इन नए पोतों के शामिल होने से भारतीय तटरक्षक बल की परिचालन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। यह कदम देश की तटीय सुरक्षा को मजबूत करने और समुद्री हितों की रक्षा सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाएगा।

वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में हुआ आयोजन

इस निर्माण समारोह की अध्यक्षता आईजी सुधीर साहनी ने की। इस दौरान भारतीय तटरक्षक बल और एमडीएल के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

आयुष दवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार के बड़े कदम, डिजिटल और जागरूकता पर जोर

नई दिल्ली, 18 मार्च।

देश में निःशुल्क आयुष दवाओं की उपलब्धता और उनके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं। आयुष मंत्रालय ने डिजिटल प्लेटफॉर्म, जागरूकता अभियानों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विस्तार के जरिए इस दिशा में काम तेज किया है, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक आयुष सेवाएं पहुंच सकें।

डिजिटल प्लेटफॉर्म से दवाओं की निगरानी

आयुष मंत्रालय ने आयुष ग्रिड के तहत आयुष अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली (एएचएमआईएस) जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किए हैं। इन प्लेटफॉर्म के जरिए आयुष केंद्रों में दवाओं की उपलब्धता का डिजिटलीकरण और निगरानी की जा रही है, जिससे चिकित्सकों और फार्मासिस्टों को बेहतर प्रबंधन में मदद मिल रही है।

राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत जागरूकता अभियान

राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के तहत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को व्यवहार परिवर्तन संप्रेषण (बीसीसी) और सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) गतिविधियों के लिए सहायता दी जा रही है। इन अभियानों के जरिए आयुष आधारित निवारक स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा दिया जा रहा है और लोगों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जनसंचार माध्यमों और शिविरों के माध्यम से समाज में आयुष पद्धतियों की उपयोगिता को व्यापक रूप से बताया जा रहा है।

आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का विस्तार

एनएएम के तहत देशभर में 12,500 आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) को कार्यशील किया गया है। इन केंद्रों के जरिए लोगों को निवारक, प्रोत्साहक, उपचारात्मक और पुनर्वास स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही, अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ रेफरल लिंकेज भी मजबूत किया गया है।

स्वास्थ्य कर्मियों को दिया जा रहा प्रशिक्षण

आयुष मंत्रालय ने आशा और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यक्रम भी शुरू किया है। इन कर्मियों को आयुष के लाभ, रोगों की रोकथाम और सामान्य बीमारियों के इलाज के बारे में प्रशिक्षित किया जा रहा है, ताकि वे जमीनी स्तर पर लोगों को बेहतर मार्गदर्शन दे सकें।

विशेष प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम

केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से 2024 और 2025 में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें मस्कुलोस्केलेटल और चयापचय संबंधी बीमारियों के प्रबंधन पर आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और सिद्ध चिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।

राज्यों को मिल रही वित्तीय सहायता

एनएएम के तहत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए वित्तीय सहायता भी दी जा रही है। राज्य सरकारें अपनी वार्षिक कार्य योजनाओं के माध्यम से प्रस्ताव भेजकर इस सहायता का लाभ उठा सकती हैं।

'आयुर्ज्ञान' योजना से भी मिल रहा सहयोग

आयुष मंत्रालय आयुर्ज्ञान योजना के तहत भी काम कर रहा है। इस योजना के जरिए आयुष कर्मियों के लिए सतत चिकित्सा शिक्षा (सीएमई) और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

लोकसभा में दी गई जानकारी

यह जानकारी प्रताप राव जाधव ने 13 मार्च 2026 को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। सरकार का उद्देश्य आयुष पद्धतियों के समग्र विकास और उनके व्यापक उपयोग को बढ़ावा देना है, ताकि आम लोगों को सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें।

भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था सभी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा कर रही है: रिपोर्ट

नई दिल्ली, 18 मार्च।

भारत में बेरोजगारी दर फरवरी में घटकर 4.9 प्रतिशत हो गई है, जो यह दिखाता है कि देश में नौकरी मिलने की रतार में सुधार हो रहा है। अब रोजगार के अवसर सिर्फ कुछ बड़े शहरों या चुनिंदा सेक्टर तक सीमित नहीं रह गए हैं।

इंडिया नैरेटिव में प्रकाशित एक लेख के अनुसार, फरवरी में मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, रिटेल, लॉजिस्टिक्स और कृषि जैसे कई सेक्टर में रोजगार बढ़ा है। इससे साफ है कि आर्थिक सुधार का फायदा अब शहरों के साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्रों तक भी पहुंच रहा है।

सरकार द्वारा बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर किया जा रहा खर्च और कारोबार में बढ़ता भरोसा अब वास्तविक नौकरी के अवसरों में तब्दील होता दिख रहा है। 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' जैसे कार्यक्रमों के तहत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के प्रयास रंग लाते दिख रहे हैं।

साथ ही, पीएलआई (प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव) स्कीम के जरिए इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे क्षेत्रों में विदेशी निवेश बढ़ रहा है। इन सेक्टर में सिर्फ फैक्ट्री में ही नहीं, बल्कि लॉजिस्टिक्स, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में भी रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं।

लेख में कहा गया है कि अब कई ग्लोबल कंपनियां भारत को अपना प्रोडक्शन बेस बना रही हैं, जिससे नौकरी के अवसर ज्यादा स्थिर हो रहे हैं और मौसमी उतार–चढ़ाव का असर कम पड़ रहा है। युवाओं के रोजगार को लेकर भी सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। टेक्नोलॉजी और डिजिटल सर्विस सेक्टर तेजी से बढ़ रहे हैं, जहां सॉटवेयर, डेटा एनालिटिक्स और क्लाउड जैसी फील्ड में लाखों लोगों को नौकरी मिल रही है।

जैसे फिनटेक, ई–कॉमर्स और ग्रीन एनर्जी . भी युवाओं के लिए नए अवसर पैदा कर रहा है। सरकार की पीएम कौशल विकास योजना जैसी स्कीम युवाओं को नए स्किल्स सिखाकर उन्हें नौकरी के लिए तैयार कर रही हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ने से यह भी संकेत मिलता है कि विकास का फायदा छोटे शहरों और गांवों तक पहुंच रहा है, जिससे लोगों की आय स्थिर हो रही है और मांग भी बढ़ रही है। लेख में यह भी कहा गया है कि सिर्फ आर्थिक सुधार ही नहीं, बल्कि लंबे समय से चल रहे बदलाव भी असर दिखा रहे हैं। खासकर, महिलाओं की श्रम भागीदारी दर में बढ़ोतरी हो रही है, जो कई सालों से स्थिर थी।

अब ज्यादा महिलाएं हेल्थकेयर, एजुकेशन, छोटे बिजनेस और डिजिटल सर्विस सेक्टर में काम कर रही हैं, जिससे रोजगार के ढांचे में बड़ा बदलाव आ रहा है। जैसे–जैसे डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ रही है, वैसे–वैसे वर्क फ्रॉम होम और पार्ट–टाइम जैसी नई नौकरी के विकल्प भी सामने आ रहे हैं, जिससे पहले बाहर रह गए लोगों को भी काम के मौके मिल रहे हैं।

इतिहास के पन्नों में 19 मार्च

नई दिल्ली, 18 मार्च।

महत्वपूर्ण घटनाचक्र

1279– मंगोलों ने चीन के सांग वंश का अंत किया।

1571– स्पेन की सैन्य टुकड़ियों ने मनीला पर कब्जा किया।

1920– अमेरिकी सीनेट ने वर्साय की संधि को खारिज किया।

1944– आजाद हिंद फौज ने पूर्वोत्तर भारत में मुख्य भूमि पर राष्ट्रध्वज फहराया।

1965– इंडोनेशिया ने सभी विदेशी तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया।

1972– भारत और बांग्लादेश के बीच में मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किया।

1982– ब्रिटेन एवं बेटिकन में 400 वर्षों के अंतराल के बाद राजनयिक संबंध स्थापित।

1990– विश्व की आईआईएचएफ अनुमोदित पहली महिला आइस हॉकी का आयोजन।

1996– बोस्निया हर्जेगोविना की राजधानी सरायेवो का पुनरू एकीकरण।

1998– अटल बिहारी वाजपेयी ने दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री का पद संभाला।

1999– यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष जैकस सांटर का अपने पद से इस्तीफ़ा।

2001– तालिबान द्वारा 100 गायों की बलि, ब्रिटेन के उच्च सदन ने संगीतकार नदीम के प्रत्यर्पण का प्रस्ताव ठुकराया।

2001– ब्रिटेन के उच्च सदन ने संगीतकार नदीम के प्रत्यर्पण का प्रस्ताव ठुकराया।2004– अमेरिका ने विश्व व्यापार संगठन में पहली बार चीन पर मुकदमा ठोका।